पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International Since 1983

हमारा मुख-पत्र वर्ष 27, अंक 1/2026

हम राजस्थानी • विजन डॉक्यूमेंट पर हो पुनर्विचार

4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की प्रदेश की राह मुश्किल

राजस्थान सरकार के विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट में 2047 तक राज्य को 4.30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जो विकसित भारत @2047 की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप बताया गया है। यह 2047 तक देश के समग्र लक्ष्य-30 ट्रिलियन डॉलर का लगभग 15 प्रतिशत है और एक असंभव लक्ष्य है। हालांकि राजस्थान के लक्ष्य का पैमाना राज्य की वर्तमान आर्थिक आधारशिला और अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति के संदर्भ में सावधानीपूर्वक आर्थिक विवेचना की मांग करता है। आर्थिक समीक्षा राजस्थान 2024-25 के अनुसार, चालू कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग 17.04 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जिससे राजस्थान भारत की सातवीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बनता है। तुलनात्मक रूप से, महाराष्ट्र का जीएसडीपी 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि तमिलनाडु और गुजरात की अर्थव्यवस्थाएं 25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र के आकार की आधी से भी कम है और तमिलनाडु या गुजरात के औद्योगिक उत्पादन से काफी छोटी है। इस पृष्ठभूमि में 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य संरचनात्मक रूप से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है।

2024-25 में राजस्थान की नाममात्र जीएसडीपी वृद्धि 12.02 प्रतिशत और वास्तविक वृद्धि 7.82 प्रतिशत आंकी गई है। हालांकि, लगभग 200 अरब डॉलर के आधार से 22 वर्षों में 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए13-13.5 प्रतिशत की सतत वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी, जो न केवल

राजस्थान की वर्तमान वृद्धि दर से कहीं अधिक है, बल्कि भारतीय राज्यों में देखी गई दीर्घकालिक औसत दरों से भी ऊपर है। इसके जवाब में, राज्य में निवेश आधारित वृद्धि पर अधिक जोर दिया है। राइजिंग राजस्थान पहल और प्रवासी राजस्थानी निवेशकों के साथ संवाद का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी पूंजी को आकर्षित करना है।

राज्य पहले से ही जस्ता और चांदी के उत्पादन में देश में अग्रणी है। ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स भी एक अन्य संरचनात्मक आधार है। बाड़मेर के पचपदरा में स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक निवेश परियोजनाओं में से एक है।

लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को भी विकास सक्षम कारक के रूप में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। जालोर में प्रस्तावित अंतर्देशीय जल बंदरगाह (कांडला बंदरगाह से जुड़ा) 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 50,000 से अधिक रोजगार सृजित कर सकता है। इससे हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मजबूती मिलेगी। राजस्थान रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत झुंझुनूं और अलवर में नोड्स के साथ रक्षा विनिर्माण में भी प्रवेश कर रहा है, साथ ही जयपुर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। इन सभी कार्य योजनाओं में राजस्थान को अन्य प्रान्तों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी जिसके लिए यहां की सरकारी व्यवस्था का कमजोर होना एक रुकावट है। यह कमजोर विजन डॉक्यूमेंट ही इसका एक प्रमाण है।

राइजिंग राजस्थान पर्यटन पोर्टल के अनुसार 2023 में राज्य में 179 मिलियन घरेलू और 1.7 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जिनका जीएसडीपी में योगदान लगभग 12 प्रतिशत है। हालांकि पर्यटन अकेले बहु-ट्रिलियन डॉलर का पैमाना नहीं दे सकता, लेकिन यह रोजगार, एमएसएमई और क्षेत्रीय समावेशन का समर्थन करता है। इस दृष्टि से, राजस्थान का विजन 2047 एक हास्यास्पद संकेत है। विवेकपूर्ण होगा कि विजन डॉक्यूमेंट पर पुनर्विचार किया जाए और यथार्थवादी लक्ष्यों के साथ नया दस्तावेज तैयार किया जाए।

प्रदीप एस महता
महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल

इस अंक में...

- पिछले 13 साल से प्रदेश में घाटे का बजट... ...3
- बिजली प्रबंधन का बनेगा नया मॉडल..............8
- पानी प्रबंधन पर पैसा ही पैसा 9
- दहलीज से कारोबार तक फैले पंख 10
- खौफ का पर्याय बनी प्रदेश की सड़कें 11

जनता की शक्ति से ही मिलता है सरकार को अधिकार! इसे कायम रखने के लिए आप हैं जिम्मेदार!!

सूरजमुखी की खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

सूरजमुखी की फसल में समन्वित कीट एवं पोषक तत्व प्रबंधन पर 20 जनवरी 2026 को छोटी सादड़ी के बंबोरी गांव में प्रगतिशील किसान मांगीलाल जणवा के खेत पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 'कट्स' के राजदीप पारीक ने बताया कि हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल फॉर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रापिक्स (इक्रीसेट) के सहयोग से भारत सरकार के नेशनल ऑइलसीड मिशन के अंतर्गत रबी सीजन में सूरजमुखी की खेती को पूरे देशभर में बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 'कट्स' द्वारा राजस्थान में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में 1000 हैक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती करवाई जा रही है। सरसों की फसल के खाली हो रहे खेत में सूरजमुखी लगाने के लिए किसानों को निशुल्क बीज दिया जा रहा है, जिसकी फरवरी के अंत तक बुआई की जा सकती है। इच्छुक किसान मांगीलाल जणवा, बंबोरी से बीज प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के जिला बीज अधिकारी रामगोपाल आर्य ने किसानों को सूरजमुखी की फसल में कीट एवं पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी दुर्गालाल ने किसानों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे नेशनल ऑयलसीड मिशन के बारे में जानकारी दी तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का आह्वान किया। 'कट्स' के मदन गिरी गोस्वामी ने बताया कि इक्रिसेट हैदराबाद से डॉ. डीएस राणा और विनय सोनकर ने सूरजमुखी के फील्ड डेमोस्ट्रेशन का अवलोकन करने के लिए रावतपुरा गांव के माखनलाल धाकड़ और विष्णु कुमार धाकड़ के खेत पर सूरजमुखी फसल का अवलोकन कर किसानों को फसल चक्र की जानकारी दी। कार्यक्रम में मांगीलाल जणवा, उत्तम धाकड़, बालकिशन, प्रह्लाद धाकड़ आदि किसानों के साथ 40 किसानों ने भाग लिया।

राजस्थान में जमीनी स्तर की परोपकारिता पर स्टेकहोल्डर्स परामर्श बैठक आयोजित

24 मार्च 2026 को भरतपुर में 'कट्स' द्वारा 'राजस्थान, भारत में जमीनी स्तर की परोपकारिता के उद्देश्यों और प्रभाव' परियोजना के तहत स्टेकहोल्डर्स परामर्श बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि कैसे स्थानीय समुदाय अपनी पहल और योगदान के माध्यम से समाज में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों, समुदाय के नेताओं और परोपकारी व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में हुई चर्चा के दौरान यह उभरकर सामने आया कि जमीनी स्तर की परोपकारिता केवल संसाधन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, नेतृत्व, समानता और समुदाय की सहभागिता को मजबूत करने का माध्यम है। बैठक में प्रतिभागियों ने साझा किया कि स्थानीय पहलें अकसर वास्तिविक और तत्काल जरूरतों से उत्पन्न होती हैं, जिन्हे समुदाय महसूस करता है, जैसे सुरक्षित पानी और भोजन की उपलब्धता, महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एवं शिक्षा और आजीविका के अवसर आदि।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि समुदाय आधारित पहलें प्रभावशाली तब होती है जब वे भरोसे, पारदर्शिता और साझा जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित हों। जब लोग अपने समाज और आसपास की जरूरतों के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनते हैं, तब न केवल स्थायी बदलाव संभव होता है बल्कि सामाजिक सहभागिता, स्वामित्व और नेतृत्व का वातावरण भी मजबूत बनाता है। प्रतिभागियों के अनुभव साझा करने के दौरान यह भी सामने आया कि सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास समुदायों में दीर्घकालिक प्रभाव का मूल आधार है। मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता इन पहलों की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

खुली चर्चा में यह बात भी उभरकर सामने आई कि जमीनी स्तर की परोपकारिता, समाज में समानता और न्याय की दिशा में योगदान करती है। स्थानीय समस्याओं को समझकर उनके स्थायी समाधान पर काम करना ही प्रभावी पहल की पहचान है। इस संवाद ने यह स्पष्ट किया कि छोटे, समर्पित और लगातार प्रयास समय के साथ बड़े और स्थायी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हैं। जब स्थानीय समुदाय सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में भाग लेता है, तब ही असमानताओं को कम करना और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना संभव होता है। इस मरामर्श ने 'कट्स' की परियोजना में स्थानीय दृष्टिकोण और अनुभवों के आधार पर दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1,200 करोड़ रुपए का निवेश अटका

राजस्थान में निवेश को लेकर सरकार के दावों के बीच सिस्टम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फ्रांस दूतावास ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर फ्रांसीसी कंपनी सैफ्लेट माल्ट इंडिया के प्रोजेक्ट को जमीन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रोजेक्ट के 'रिस्क' में आने की आशंका तक जता दी है।

दूतावास की ओर से लिखे पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सीएम स्तर पर सकारात्मक बातचीत होने और सहमति बनने के बाद रीको ने जमीन नहीं दी। जमीन आवंटन के लिए जो कीमत प्रस्तावित की है वह पहले तय दर से काफी अधिक है साथ ही आवंटन की समय सीमा भी बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी है। इससे प्रोजेक्ट के लिए जोखिम की स्थिति बन गई है और निवेश को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। *(रा.प., 28.03.26)*

मनरेगा में सामने आई कई गड़बड़ियां

केंद्र सरकार ने मनरेगा की जमीनी हकीकत जानने के लिए 25 राज्यों के 55 जिलों में जब औचक जांच कराई, तो जांच में 11 लाख 04 हजार 627 वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। इस दौरान तीन अरब रुपए से अधिक की राशि हड़पने का खेल सामने आया।

घोटाले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार को तत्काल रिकवरी के निर्देश जारी करने पड़े। अब तक 302.45 करोड़ रुपए में से 273 करोड़ रुपए की वसूली हो सकी है। इससे साफ है कि गरीबों के रोजगार व हक की रकम को लूटा गया। योजना की हकीकत जानने के लिए 55 जिलों में एक हजार से अधिक स्थानों पर टीमें भेजी गई थीं। *(रा.प., 12.01.26)*

कागजों में दबा अवैध खनन

राजस्थान में अवैध खनन और अवैध खनन सामग्री के परिवहन पर खान विभाग की सख्ती फाइलों तक सिमटकर रह गई है। पिछले 15 वर्षों में विभाग के नियमों के उल्लंघन पर 2,907 करोड़ रुपए का जुर्माना तो लगाया, लेकिन वसूली के नाम पर सिर्फ 924 करोड़ रुपए ही जमा हो सके।

हालात यह है कि विभाग में जुर्माना लगाने की औपचारिकता तो पूरी की जा रही है, लेकिन वसूली के लिए न तो इच्छा शक्ति दिख रही है और न ही ठोस कार्रवाई। नतीजा यह है कि खनन माफिया बेखौफ होकर अपनी जेब भरने में लगा है, जबकि सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। यदि बकाया 1983 करोड़ रुपए की वसूली हो जाए तो इससे सड़क, पुल, शहरी और ग्रामीण विकास के कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। *(रा.प., 09.02.26)*

किसानों का यूरिया कारखानों में?

अन्नदाता की मेहनत पर खाद-बीज का 'काला' खेल पानी फेर रहा है। हाल ही कृषि विभाग ने जयपुर में सांगानेर स्थित मुहाना मंडी क्षेत्र में छापा मारा तो किसानों को अनुदान पर सप्लाई होने वाले यूरिया को ब्लैक में खरीदकर डीजल वाहनों में इस्तेमाल होने वाला डेफ बनाने का मामला सामने आया।

छापे में अनुदानित यूरिया के1154 कट्टे जब्त किए गए। विभाग अवैध भंडारण करने वाले दिनेश शर्मा से पूछताछ कर रहा है कि यूरिया उस तक कैसे पहुंचा? गौरतलब है, अनुदानित यूरिया का औद्योगिक उपयोग प्रतिबंधित है और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सेक्शन 25 के तहत दंडनीय अपराध है। *(रा.प. एवं दै.भा., 08.03.26)*

पिछले 13 साल से प्रदेश में घाटे का बजट...

प्रदेश में सीएजी के अनुसार गत 13 वर्ष से लगातार कमाई से ज्यादा खर्चा करने यानी घाटे का अनुमान लगाकर बजट पेश किया जा रहा है और कर्ज को कमाई में शामिल किया जा रहा है। स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण के लिए कर्ज लेना सही माना जाता है, लेकिन प्रदेश में स्थिति यह है कि विकास पर कर्ज की आधी राशि भी खर्च नहीं हो रही।

पिछले वित्तीय वर्ष में तो सरकार को 210 बार रिजर्व बैंक से तय सीमा से अधिक राशि निकालनी पड़ी। कर्ज लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि मार्च के अंत तक कुल देनदारी 7,26,384 करोड़ रुपए हो जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने रिजर्व बैंक से 1,22,280 करोड़ रुपए एडवांस लिया, जिस पर 180 करोड़ रुपए ब्याज दिया। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रेल से सितंबर 2025 तक 35,826 करोड़ रुपए की देनदारी बढ़ने से प्रदेश पर कुल उधारी 6,76,513 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। *(रा.प., 10.02.26)*

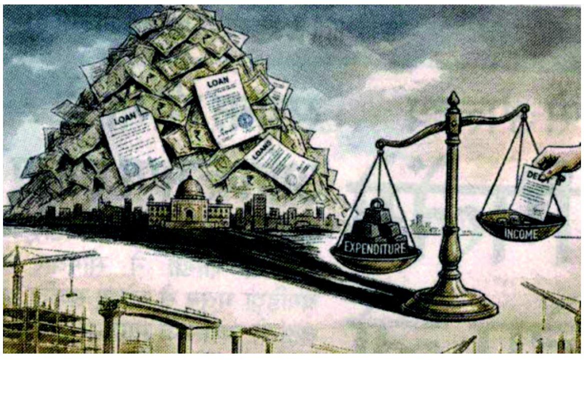

राजस्थानः निर्यात की गति धीमी

राजस्थान का निर्यात ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन निर्यात की तैयारी उतनी मजबूत नहीं होने से प्रदेश निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) रैकिंग में पिछड़ गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में राजस्थान का निर्यात 77,771 करोड़ से बढ़कर 97,171 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

राजस्थान को रैकिंग सुधार के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे। सरकार को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करना होगा तथा लॉजिस्टिक लागत घटाने के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा। साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चैन से जोड़ना होगा। नीति आयोग के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र राजस्थान के लिए चुनौती बने हुए हैं। ज्यादातर कंपनियां-निवेशक वहां जा रहे हैं। *(रा.प., 17.01.26)*

वादे पूरे करने से बचती हैं सरकारें

राजनीतिक दलों और नेताओं के चुनावी वादे पूरे नहीं करना अक्सर बहस का विषय बनता है। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में खुद सांसदों को दिए गए सभी आश्वासन ही सरकारें पूरी नहीं करे, तो व्यवस्था व विश्वसनीयता पर सवाल उठता है।

पिछले 22 सालों में संसद में दिए आश्वासनों के अमल पर पत्रिका की पड़ताल से सामने आया कि सांसदों से किए गए 34,301 आश्वासनों में से 5,556 आश्वासन पूरे नहीं किए गए। संसद के पटल पर मंत्री का बयान 'आश्वासन' कहलाता है, जिसे पूरा करने की बाध्यता है। मसलन पुलवाना हमले की जांच, कालाधन, भीड हिंसा डेटा, अडानी-सेवी जांच और स्मार्ट फेंसिंग (सीमा सुरक्षा)। ये पांच प्रमुख ड्रॉप मामले हैं, इन पर ससंद में खूब चर्चा तो हुई पर वादे पूरे नहीं हुए...।

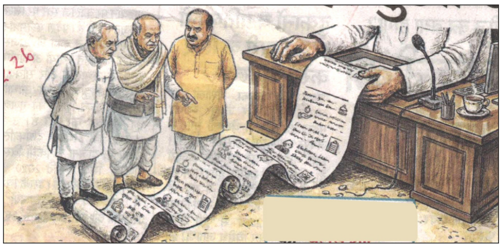

(रा.प., 09.02.26)

फर्जी डिग्री से हासिल की नौकरी

प्रदेश में बड़े पैमाने पर कई निजी विश्वविद्यालयों की ओर से फर्जी डिग्रियां देकर जेब भरी जा रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। फर्जी डिग्री के आधार पर बड़ी संख्या में अयोग्य युवा सरकारी सेवा में आ चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार के पास अब तक स्पष्ट जानकारी तक उपलब्ध नहीं है।

उच्च शिक्षा विभाग इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। राजस्थान विधानसभा में भी इस बारे में सवाल उठ चुका है। लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं आया। सरकार को इस बारे में ठोस कार्रवाई करते हुए गहन जांच करानी चाहिए। यह अपराधिक कृत्य है। योग्य युवा रोजगार के लिए दर-दर भटकते फिर रहे हैं और फर्जी डिग्री प्राप्त कर अयोग्य लोग सरकारी व गैर सरकारी पदों नियुक्त है।

(रा.प., 23.02.26)

बना रहे फर्जी कृषक प्रमाण पत्र

प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सरकारी स्टाम्प पेपर और नोटरी सील का दुरुपयोग करके फर्जी कृषक प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस खेल में विभागीय मिलीभगत और दलालों का नेटवर्क सक्रिय है। जैसलमेर जिले की साकड़ा तहसील के साथ कई स्थानों पर फर्जी कृषक प्रमाण बनाने का गिरोह सक्रिय है।

पत्रिका की टीम ने पूरे प्रकरण की जांच की तो सामने आया कि फर्जी तरीके से सैकड़ों की संख्या में कृषक प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। इन प्रमाण पत्रों में तहसीलदार और पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर हैं। सील भी फर्जी लगी है। सामने आया कि दलालों का नेटवर्क कुछ हजार रुपए में प्रमाण पत्र दिलवा रहा है। यह ही नहीं मात्र 25 हजार रुपए में वे किसी को भी जमीन का मालिक बना देते हैं। पत्रिका ने यह खुलासा पहले भी किया है। यह जांच का विषय है कि प्रमाण पत्र के जरिए लोग कहीं सरकारी योजनाओं का गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं।

(रा.प., 28.01.26)

किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जी भूमिधारक बनकर जालसालों ने 440 करोड़ रुपए हड़प लिए। यह आंकड़ा प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आया है। राज्य स्तर पर फर्जीवाड़ा उजागर होने पर राज्य व केंद्र सरकार ने छह लाख संदिग्ध किसान चिन्हित किए हैं और उनकी किस्त रोक दी है।

अब संदिग्ध खाताधारकों का फिजीकल वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए केंद्र सरकार एसओपी तैयार कर रही है। सरकार ने किसानों के लिए फार्मर आई डीकार्ड जारी किए हैं। यह कार्ड उन किसानों के लिए है, जिनके नाम जमीन है। इसके डेटा को पीएम सम्मान निधि के डेटा से क्रास चेक किया गया है। फार्मर आईडी नहीं होने वालों को संदिग्ध माना गया है। इसके साथ जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद दोबारा एक्टिव किया गया, उन सभी को भी संदिग्ध माना गया है।

(दै.भा., 23.03.26)

प्रदेश की जनता पर करोड़ों की देनदारी

राजस्थान के बजट में राजस्व के हवाई अनुमान लगाकर घोषणाओं की रेवड़ियों (फ्री बीज) से आमजन का दिल जीता जा रहा है, लेकिन बढ़ते कर्ज से प्रदेश की कमर टूट रही है। अधिकारी बजट पूर्व बैठकों के आधार पर राजस्व का जो अनुमान लगाते हैं, वह वास्तविकता से हजारों करोड़ रुपए दूर है।

मौजूदा वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति के वास्तविक आंकड़े अनुमान से कितने पीछे रहेंगे, यह तो अगले साल ही पता चलेगा। फिलहाल साल-दर-साल अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक आबादी पर कुल देनदारी 7.92 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएगी।

(रा.प., 27.02.26)

मिड डे मील घोटाला: 2023 करोड़ हजम

राज्य की मिड डे मील योजना में करीब 2,023 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला हुआ है। उक्त राशि से विद्यार्थियों को 3.12 करोड़ कॉम्बो पैकेट उपलब्ध करवाना बताया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कॉनफैड के अधिकारियों, केंद्रीय भंडार के अफसरों और निजी फर्मों सहित 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इन आरोपियों में कांग्रेस सरकार में गृहराज्य मंत्री रहे राजेन्द्र यादव के दो पुत्रों व कुछ रिस्तेदारों के भी नाम बताए जा रहे हैं। पांच आइएएस समेत 40 अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध होना सामने आया है। एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार मामला कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

(रा.प., 09.01.26)

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं मे संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

बदल रही प्रकृति की चाल

प्रकृति के साथ लगातार हो रहे खिलवाड़ के कारण अब आबोहवा बदलने लगी है। कभी सर्दियों के बाद बागों में खिलते फूल और आम के बौर से बसंत के आगमन का संकेत मिलता था, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण बसंत व हेमंत जैसी ऋतुएं सिकुड़ रही हैं। अब सर्दी के बाद सीधे गर्मी आ रही है।

वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ट्रांजिशन पीरियड, यानी ऋतु परिवर्तन का समय लगातार छोटा हो रहा है। भोपाल के बैज्ञानिक डॉ. पंकज कुमार के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर खतरा है। एक अध्ययन के मुताबिक प्रथ्वी का तापमान पिछले 1000 वर्षों में जितना (1 डिग्री) बढ़ा था, उतना अब मात्र 100 वर्षों में बढ़ गया है। इसका कारण बिजली संयंत्रों और ऑटो-मोबाइल से निकलने वाला अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। *(रा.प., 23.03.26)*

अटल ज्ञान केंद्र होंगे विकसित

प्रदेश में ग्रामीण युवाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 1687 अटल ज्ञान केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

अटल ज्ञान केंद्र योजना के तहत स्थापित किए जा रहे इन केंद्रों को ग्रामीण युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए सभी केंद्रों में निर्धारित अधोसंरचना, डिजिटल सुविधाएं एवं अध्ययन संसाधन समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। *(दै.भा.,10.02.26)*

स्वरोजगार से प्रदेश के युवा बनेंगे उद्यमी

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। योजना के तहत प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जारी गाइडलाइन के अनुसार योजना में शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। साथ ही 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सूक्ष्म व लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क का पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में की थी। *(रा.प., 17.01.26)*

वर्ष 2047 तक विकसित होगा भारत

भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक एक समृद्ध और उच्च आय वाला राष्ट्र बनने की राह पर है। वाशिंगटन एग्जामिनर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत 'मिडिल इनकम ट्रैप' (मध्यम आय के जाल) को तोड़ने में सक्षम है, जिसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की जैसी अर्थव्यवस्थाएं फंस कर रह गई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार 2003 के बाद से भारत की औसत ग्रोथ 7% फीसदी से अधिक रही है। यदि भारत अगले दो दशकों तक अपनी 7% की औसत विकास दर बरकरार रखता है, तो इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 15000 डालर (वर्तमान मानकों में) के पार पहुंच जाएगी। इस तरक्की के चार स्तंभ डेमोग्राफिक डिविडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, डिजिटल क्रांति और चीन से मोह भंग होना माने जा रहे हैं। *(रा.प., 23.03.26)*

अरावली पर्वतमाला में बनी दरारें

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से किए गए क्रमिक उपग्रह आधारित अध्ययनों और जारी रिपोर्ट ने चिंताजनक खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरावली पर्वत माला में बनी 12 बड़ी दरारों के जरिए रेगिस्तानी रेत पूर्व की ओर बढ़ रही है। वर्ष 2005-07 के बाद अरावली की रेगिस्तान रोकने वाली क्षमता में तेज गिरावट दर्ज की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौर में खनन, शहरी विस्तार और वनों की कटाई चरम पर पहुंच गई। पहले राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी अपने अध्ययन में इस बात का खुलासा किया था कि आने वाले वर्षों में रेगिस्तान से उठने वाले रेत के तूफान एनसीआर तक पहुंच सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा भी था कि अरावली संकट पर स्थायी विज्ञान आधारित समाधान अति आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय अरावली प्राधिकरण बनना चाहिए। *(रा.प., 20.01.26)*

केंद्रीय बजट- 2026-27

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। बजट विकसित भारत के निर्माण, चहुंमुखी समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ते कदमों का पथ दिग्दर्शन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करेगा।

बजट में खेती और अन्नदाता को खास अहमियत दी गई है। वित्तमंत्री ने बहुभाषी एआई टूल 'भारत विस्तार' के जरिए डिजिटल कृषि क्रांति की नींव रखकर, उत्पादकता दोगुनी करने, जोखिम घटाने और किसानों की आय बढ़ाने का रोडमैप पेश किया है। साथ ही, ग्रामीण स्तर तक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

बजट में युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा स्किल डवलपमेंट को एक साझा रणनीति से जोड़कर, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अनुसंधानों पर विशेष जोर रहेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने जैसी कई घोषणाएं बजट में शामिल की गई है।

'भारत विस्तार' रखी डिजिटल कृषि क्रांति की नींव

केंद्रीय बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले बजट से 7% ज्यादा है। वित्त मंत्री द्वारा 'भारत विस्तार' नाम से एआइ कृषि प्लेटफार्म शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे कृषि में डिजिटल क्रांति के जरिए किसानों को खेती से संबधित सभी जानकारियां एवं सुविधाएं मिल सकेंगी। किसान जागरूक होंगे और खेती में नवाचार आएंगे। बजट में किसान की उत्पादकता बढ़ाने का एवं उसे अपनी फसल का सही लाभ दिलाने के प्रयास किए गए हैं।

भारत होगा मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब

केंद्रीय बजट में पहली बार स्वास्थ्य का बजट 1 लाख 4 हजार 500 करोड़ को पार कर गया है। देश में आयुर्वेद के 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में 24 घंटे चलने वाले इमरजेंसी और ट्रोमा केयर सेंटर बनेंगे। पांच रीजनल मेडिकल हब तैयार होंगे। मेडिकल शिक्षा में इलाज, रिसर्च एक साथ होगी। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के साथ आधुनिक जांच व पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अगले 5 साल में 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेंड किया जाएगा। वे लंबे समय तक बुजुर्गों की देखभाल व स्वास्थ्य जरूरतें पूरी करेंगे। माना जा रहा है कि अब भारत मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब बनेगा।

शिक्षा क्षेत्र बनेगा रोजगारोन्मुखी

केंद्र सरकार के बजट में शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 800 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की पढ़ाई और सुरक्षा को मजबूती दी जाएगी। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगे, जो इंडस्ट्री, शिक्षा, रिसर्च के इंटीग्रेटेड हब होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए बजट में और भी कई घोषणाए की गई हैं।

महिला उद्यमिता को दिया प्रोत्साहन

केंद्रीय बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे कई प्रावधान हैं। महिला उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए से 'शीमार्ट प्लेटफॉर्म' स्थापित होगा। स्टार्टअप व एमएसएमई क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को कई सुविधाएं मिलेंगी। 'लखपति दीदी' योजना का दायरा बढ़ेगा।

बुनियादी ढांचे को दी बड़ी प्राथमिकता

केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12.21 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। जो पिछले साल की तुलना में लगभग 9% अधिक है। जिसमें सड़क रेलवे और ऊर्जा एवं जल प्रदाय परियोजनाओं पर खास ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में 7 नए हाई-स्पीड रेलवे कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई है। पर्यावरण व ऊर्जा के लिए केंद्रीय बजट में 25000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

एमएसएमई को दिया बढ़ावा

केंद्रीय बजट में एमएसएमई और उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है। जिसमें छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। आर्थिक सवृद्धि हेतु एक रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जिसके अतंर्गत विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेत ग्रामीण स्तर तक कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निवेश, निर्यात और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

राजस्थान बजट- 2026-27

राज्य विधानसभा में वित्तमंत्री दिया कुमारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। उन्होंने प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बजट में अच्छे प्रावधान रखे हैं। वित्तमंत्री ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगों को बढ़ावा देने और साथ ही बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास पर खास नजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर, विकसित राजस्थान का संकल्प व्यक्त किया है।

मानना है, भारत के हर गांव व हर राज्य पूर्ण विकसित होंगे तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रदेश में डबल इंजन सरकार होने से जनता भी उत्साहित है और उसे भरोसा है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई कसर नहीं रहने देंगे। बजट घोषणाओं को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आवश्यक है। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

किसान होंगे तकनीकों से सशक्त व समृद्ध

राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने खेती और किसानों के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बजट में प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए अनुदान व ऋण सुविधाओं में इजाफा करने के साथ ही उत्पादकता बढ़ाने, कृषि को नई तकनीकों से जोड़ने, सिंचाई, बीज, बिजली, कृषि यंत्रीकरण, भंडारण और प्रोसेसिंग के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणाएं कर, खेती और किसानों को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए सार्थक कदम बढ़ाए हैं। माना जा रहा है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे।

स्वास्थ्य एवं उपचार को खास अहमियत

राजस्थान के बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। उदयपुर को मेडिकल हब बनाने, गंभीर मरीजों व सड़क हादसों के मामलों में त्वरित इलाज, मानसिक स्वास्थ्य के उपचार की व्यवस्था, 'मां' फंड में इजाफा करने, निःशुल्क जांच और दवाइयों के लिए 3500 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने एवं जन स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं में बजट प्रावधान बढ़ाकर कई सुविधाएं देने की घोषणाएं की गई हैं। बजट में 32 हजार 526 करोड़ रुपए की राशि अस्पतालों के विस्तार, नए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आइपीडी सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में लगाई जाएगी। ट्रामा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

शिक्षा को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा

राजस्थान के बजट में शिक्षा को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के जरिए एक लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे शिक्षा के साथ युवा रोजगार देने वाले बनेंगे। मेधावी छात्रों को टैबलेट/लेपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए का ई-वाउचर दिया जाएगा। स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। तीस करोड़ रुपए की लागत से नवीन टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। कॉलेज छात्रों के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाने 11 नए महाविद्यालय और 2 कृषि महाविद्यालय खोले जाने के अलावा उच्च शिक्षा में अनुसंधानों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर

राजस्थान के बजट में महिलाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना में विस्तार कर महिलाओं को कम ब्याज दर पर 1.50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकेगा। स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को भी कम ब्याज दर पर एक करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा मिलेगी। महिला मित्र योजना के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक महिला मित्र नियुक्त की जाएगी। महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट बनवाएं जाएंगे। शिक्षा और आवासीय सुविधाओं के लिए भी बजट में कई प्रावधान कर महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान

राजस्थान के बजट में विकास को तेज गति दिए जाने के लिए वित्त मंत्री का ध्यान सड़क, जल आपूर्ति, ऊर्जा, ग्रामीण व शहरी विकास, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रहा है। इसके लिए बजट में बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय कर नई-नई योजनाओं की घोषणाएं की गई है। इससे शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण औद्योगिक विकास को तेजी से बल मिलेगा।

बजट में अन्य राहतभरी खास घोषणाएं

- राजस्थान के बजट में 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने, फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मिशन राजगिफ्ट और पशुपालकों को उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा।
- राजस्थान में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत शहरों के आसपास के 6,245 गांवों को शामिल किया गया है। इस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर जल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष में 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।
- राजस्थान के बजट में 3496 पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाए जाने की घोषणा से जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। अगले साल 50 हजार सोलर पम्प लगाकर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

थमने का नाम नहीं ले रही बिजली चोरी

प्रदेश में बिजली चोरी का सिलसिला थम ही नहीं रहा। पिछले दस माह में ही करीब 62 हजार लोगों ने 229 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी कर ली। वसूली आधी राशि की भी नहीं हो सकी है। कई कानूनी दाव-पेच में फंस गए हैं तो कई में डिस्कॉम धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहा है।

सबसे गंभीर बात यह है कि चोरी हुई बिजली का भार बिजली टैरिफ दर (जिसकी वसूली नहीं हुई) में जुड़ता रहा है। इससे ईमानदार उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही डिस्कॉम्स की आर्थिक कमर भी टूट रही है और घाटा बढ़ता जा रहा है। बिजली खरीद राशि चुकाने के लिए लगातार लोन लिया जा रहा है। यही लोन राशि भी जनता से बिजली की बढ़ी दर के रूप में ली जाती रही है। यह सब प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी के चलते हो रहा है। *(रा.प., 14.02.26)*

ग्रीन हाइड्रोजन से बदलेगी तस्वीर

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन पर बढ़ता राष्ट्रीय फोकस राजस्थान के लिए नए अवसर खोल सकता है। देश की पहली हाइड्रोजन पॉलिसी (क्लीन एनर्जी) यहां लागू हो चुकी है। अडानी टोरेंट पावर सहित छह बड़ी कंपनियां प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में है।

सौर एवं पवन ऊर्जा की अपार संभावनाओं के चलते राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन सकता है, जिससे निवेश और रोजगार को नई गति मिलेगी। आने वाले वर्षों में ऊर्जा और परिवहन की दिशा तेजी से बदलने वाली है। हाइड्रोजन से चलने वाले ड्रोन, स्कूटर और गोल्फ कार्ट पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम है। यह राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

(रा.प., 29.01.26)

उपभोक्ता लगा सकेंगे हाइब्रिड इन्वर्टर

प्रदेश में रूफटाप सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता सोलर प्लांट के साथ अब हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगा सकेंगे। इससे सोलर से बनी अतिरिक्त बिजली को स्टोरेज सिस्टम में बचा सकेंगे। सोलर सिस्टम से बनी अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोरेज कर जरूरत के समय उपयोग किया जा सकेगा।

जयपुर डिस्कॉम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे नेट मीटरिंग, ग्रॉस नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग के तहत सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को हाईब्रिड इन्वर्टर लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उपकरणों का निर्धारित सुरक्षा मानकों और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना जरूरी होगा। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार रूफटॉप सोलर सिस्टम में बैटरी स्टोरेज, छोटे विंड हाइब्रिड और सोलर ट्रेकर जैसे अतिरिक्त तकनीकी विकल्प भी जोड़े जा सकते हैं।

(रा.प., 06.03.26)

वाटर बैटरीः पानी में होगी बिजली स्टोर

देश में तेजी से बढ़ रही ग्रीन ऊर्जा के साथ ही सबसे बड़ी चिंता उसे स्टोर कर कम उत्पादन वाले समय में उपयोग करना है। इसे देखते हुए बैटरी स्टोरेज के साथ केंद्र वाटर बैटरी विकसित करने में जुट गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2035 तक 5.8 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 100 गीगावाट पानी आधारित पंप बिजली स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य रखा है।

रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पंप स्टोरेज विकास में अग्रणी है। वहीं राजस्थान, ओडिसा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में शाहपुर, सिरोही, ब्राह्मणी और सुखपुरा जैसे क्षेत्रों में लगभग 6.160 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं सर्वे और जांच चरण में हैं। इससे स्थानीय स्तर पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। राज्य में 2034-35 तक कुल 11,323 मेगावाट स्टोरेज क्षमता विकसित होने की संभावना है।

(रा.प., 25.01.26)

विद्युत निगमों ने 9400 करोड़ रुपए ज्यादा वसूले

बिजली बिलों में लगाए जा रहे ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को लेकर बड़ा वित्तीय अंतर सामने आया है। आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आया कि विद्युत निगमों द्वारा अप्रेल से दिसम्बर 2025 के बीच उपभोक्ताओं से 9,400 करोड़ रुपए अधिक वसूले गए।

प्रदेश में उपभोक्ताओं के बिलों में यह राशि समायोजित होनी चाहिए। लेकिन विद्युत निगमों के पास इसके लिए कोई प्लान नहीं है। विषय विशेषज्ञों के अनुसार ईंधन अधिभार की दर गणना सही नहीं है। ईंधन अधिभार का निर्धारण केवल ऊर्जा प्रभार पर प्रति यूनिट के आधार पर होना चाहिए। बिजली खरीद और वसूली की स्थिति में भी काफी अंतर सामने आया है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच भी वास्तविक अधिभार कम रहा है। इन सभी का समायोजन बिलों में होना चाहिए। विद्युत निगमों को उपभोक्ताओं को यह अंतर राशि लौटाई जानी चाहिए।

(रा.प., 11.03.26)

बिजली प्रबंधन का बनेगा नया मॉडल

राजस्थान में तेजी से बढ़ रही सौर ऊर्जा के कारण बिजली उत्पादन और खपत के संतुलन को बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने 'डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी और डिमांड साइड मैनेजमेंट नियम 2026' का मसौदा तैयार किया है।

इस मसौदे का उद्देश्य बिजली की मांग को बेहतर तरीके से प्रबंध कर बिजली खरीद लागत कम करना और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले टैरिफ बोझ को घटाना है।

जो उपभोक्ता अपनी बिजली डिमांड को डिस्कॉम की जरूरत और बिजली की उपलब्धता के अनुरूप शिफ्ट करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में बिजली बिल में छूट दी जाएगी। इसके लिए डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी सेल बनाया जाएगा। यह सेल ऐसे प्लान करेगा, जिससे बिजली की खपत को पीक समय से हटाकर सस्ती बिजली वाले समय में शिफ्ट किया जा सके। विनियामक आयोग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(रा.प., 17.03.26)

बिजली छीजत, बिजली चोरी ! उपभोक्ता पर है दोनों भारी !!

दूषित जल से 60 करोड़ लोग संकट में...

देश का लगभग 70% पेयजल दूषित है। पानी की गुणवत्ता में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। देश में 60 करोड़ लोग अत्यधिक या गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। ये आंकड़े इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनिबिलिटी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दर्ज है।

वर्ष 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे करोड़ों लोगों के सामने ज्यादा संकट खड़ा होने वाला है। इससे देश की जीडीपी का 6% तक नुकसान हो सकता है। मई 2023 में भूजल के 15,259 नमूनों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार 19.8% सैंपल में नाइट्रेट तय सीमा से ज्यादा था। 9.04% में फ्लोराइड और 3.55% में आर्सेनिक तय मात्रा से ज्यादा था। कुछ में आयरन 13.20%, फ्लोराइड 3.07%, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 7.25% और यूरेनियम 6.60% अधिक पाया गया था। *(दै.भा., 03.01.26)*

गांवों में होगी पानी की डिजिटल मैपिंग

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अब पानी के स्रोत से लेकर नल तक सप्लाई तंत्र की डिजिटल मैपिंग होगी। इसके लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा 'सुजलम भारत' तैयार होगा। हर गांव को यूनिक 'सुजल गांव सर्विस एरिया आईडी मिलेगी।

ग्राम पंचायत और जल एवं स्वच्छता समिति योजना शुरू होने और हस्तांतरण प्रक्रिया में 'जल अर्पण' कार्यक्रम के तहत शामिल रहेंगी। ग्राम पंचायत काम पूरा होने का प्रमाण देगी। राज्य सरकार जब यह सुनिश्वित कर देगी कि गांव संचालन-रखरखाव की पूरी व्यवस्था है, तभी पंचायत 'हर घर जल' घोषित हो सकेगी। विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रख जेजेएम 2.0 गांवों में चौबीसों घंटे पानी सप्लाई पर काम करेगा। *(दै.भा., 11.03.26)*

खत्म हो रहा धरती का 'ब्लू गोल्ड'

दुनिया 'वाटर स्ट्रेस' यानी जल संकट से 'वाटर बैंक्रेप्सी' यानी जल दिवालियापन के युग में है। संयुक्तराष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनवी) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इंसान मीठे पानी के स्त्रोतों का इस कदर दोहन कर रहा है कि अब उनका उबरना नामुमकिन सा हो गया है।

यूएनवी की रिपोर्ट के अनुसार हमने अपनी जमा पूंजी यानी भूजल और प्राकृतिक जलाशय पूरी तरह लुटा दिए हैं। इससे चार अरब लोग साल में कम से कम एक महीना भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। एक चौथाई आबादी उन जलाशयों पर निर्भर हैं, जिनका आधा पानी 1990 के बाद सूख चुका है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि अभी वैश्विक निगरानी ढांचा तैयार नहीं किया, तो अच्छी बारिश के दिनों में भी दुनिया पानी के लिए संघर्ष करती रहेगी।

(रा.प., 22.01.26)

हर घर जल की दिशा में बड़ा कदम

जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइड लाइंस के अनुसार राजस्थान ने जल शक्ति मंत्रालय से एमओयू कर लिया है। इस एमओयू के बाद प्रदेश के बकाया 44.65 लाख घरों में नल से जल मिल पाएगा। जल जीवन मिशन 1.0 में 1 करोड़ 7 लाख घरों में से केवल 63.03 लाख ग्रामीण घरों में ही नल कनेक्शन हो पाए थे।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने जेजेएम की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही जेजेएम के पुनर्गठन के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है, जिसमें कुल केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि यह एमओयू प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ व नियमित जल सप्लाई करने, सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने और समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की भूमिका निभाएगा। *(दै.भा., 18.03.26)*

भूजल संरक्षण पर खड़े हो गए सवाल

प्रदेश में भूजल संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भूजल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण पिछले छह महीनों से नए नियम और रेगुलेशन तैयार नहीं कर पाया। इसका सबसे ज्यादा असर डॉर्क जोन क्षेत्रों पर पड़ रहा है। इन इलाकों में बिना रोक-टोक भूजल का दोहन जारी है। जिससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है।

हालात यह है कि प्रदेश में 150 प्रतिशत भूजल दोहन हो रहा है। प्रदेश में 214 ब्लॉक अतिदोहित है। भूजल दोहन चार्जेज से मिलने वाले 500 करोड़ रुपए का भी प्रदेश को नुकसान हो रहा है। राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्रधिकरण विधेयक -2024 को विधान सभा में 10 सितंबर 2025 को पारित कर दिया था। इससे पहले दो बार विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया था, इसके बाद 5 महीने पहले राज्यपाल से मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अधिकारियों ने इसे दबा रखा है। *(दै.भा., 20.03.26)*

पानी प्रबंधन पर पैसा ही पैसा

देश में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में जयपुर को जल प्रबंधन और सीवेज-ड्रेनेज में सुधार का 'लाइफ जेकेट' देने का वादा किया गया है। शहरी बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने के लिए खजाना खोला जाएगा। राजधानी को सीवेज-ड्रनेज और जल प्रबंधन सुधार के लिए अहम शहर के रूप में चिन्हित किया गया है।

वित्त आयोग की सिफरिशों के लागू होने पर जयपुर में शेष शहरी इलाकों में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार, मौजूदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने से लेकर ट्रीटेड पानी का पार्क, उद्योगों और निर्माण कार्यों में उपयोग करने के लिए सिस्टम विकसित कर सकें गे। राजधानी पर इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि जयपुर का तेजी से शहरी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। सीवरेज नेटवर्क का पूर्ण कवरेज अभी भी चुनौती बना हुआ है। बरसात के मौसम में जलभराव जैसी कई समस्याएं हैं। *(रा.प., 04.02.26)*

दहलीज से कारोबार तक फैले पंख

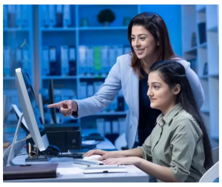

औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्यम स्थापना के लिए प्रदेश की करीब 3600 महिलाओं ने आवेदन किया है। इसमें जयपुर और चूरू जिले में 200 से अधिक महिलाएं हैं। 15 जिले ऐसे है जिनमें आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मुताबिक कुछ समय से योजनाओं के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। जिससे स्पष्ट होता है औद्योगिक क्षेत्र में लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। स्वरोजगार के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिलाया जाता है। बजट में 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। *(रा.प., 08.03.26)*

'लखपति दीदी' बन रही उभरती पहचान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजीविका हमारी बहनों के सशक्तीकरण, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की अहम कड़ी के साथ ही गांवों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन रहा है। सरकार का संकल्प है कि 'हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार' मिले।

जयपुर में लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लखपति दीदियां अग्रणी राजस्थान की उभरती हुई पहचान बन चुकी है और अगला लक्ष्य मिलेनियर बनना है। इसमें राजीविका सबसे प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है। अब तक प्रदेश में 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है।

(रा.प., 22.12.25 एवं दै.भा., 14.01.26)

एग्री-बिजनेस में बेटियों का बढ़ा रुझान

राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों में लगभग 57 प्रतिशत छात्र और 43 प्रतिशत छात्राएं अध्ययनरत हैं। बालिकाओं की 40 प्रतिशत से अधिक भागीदारी यह संकेत दे रही है कि बेटियां भी खेती और एग्री-बिजनेस के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही हैं। 12वीं कक्षा के बाद कृषि विषय से पढ़ाई कर छात्र-छात्राएं कृषि क्षेत्र में सफल कॅरियर बना सकते हैं।

अब डिप्लोमा या पूर्ण डिग्री पाठ्यक्रम के माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीकों, कृषि व्यवसाय और कृषि पद्धतियों में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। 12वीं (सांइस स्ट्रीम) के बाद बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या हॉर्टिकल्चर जैसे स्नातक पाठ्यक्रम बेहतर विकल्प हैं। इसके लिए होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में आइसीएआर, सीयूईटी और एमसीएईआर सीईटी शामिल हैं। *(रा.प., 28.02.26)*

मिसाल बन रही आदिवासी महिलाएं

प्रदेश के वागड़ क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भरता में नई मिसाल कायम कर रही हैं। वे बैंकों से लिए गए कर्ज को भी समय पर चुका रही हैं। प्रदेश में जारी रैंकिंग में वागड़ जिले बेहतर स्थिति में हैं। झुंझुनूं पहले, डूंगरपुर दूसरे व बांसवाड़ा तीसरे स्थान पर है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़कर यहां की आदिवासी महिलाएं बैंकों से ऋण लेकर अलग अलग व तरह-तरह के छोटे उद्योग शुरू कर सफल उद्यमी बन रही हैं। सालभर में जिले की 70 हजार 704 महिलाओं ने एसएचजी के माध्यम से 'लखपति दीदी' बनने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। *(रा.प., 12.03.26)*

महिलाएं ले रही रोजगार के लिए ऋण

पिछले पांच सालों में छोटे कारोबारों के लिए ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर दोगुनी से भी अधिक हो गई है। इनमें रिटेल व्यवसाय के लिए ऋण लेने वाली महिलाएं 2.14 गुना और छोटे व मझोले कारोबार (एमएसएमई) के लिए ऋण लेने वाली 2.62 गुना बढ़ी है। अब स्टैंडअप इंडिया स्कीम में महिलाओं की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के छोटे कारोबारों पर मुद्रा योजना का असर जानने के लिए दो अलग-अलग अध्ययन कराए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के 2018 के राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार, 2015 से 2018 के बीच मुद्रा योजना से करीब 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा हुए हैं। बिजनेस लोन के क्षेत्र में महिलाओं की 2019 में हिस्सेदारी जो 9 फीसदी थी बढ़कर 2024 में 16 फीसदी हो गई है। *(दै.भा., 03.02.26)*

नारी शक्ति की भूमिका सबसे अहम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में नारी शक्ति की भूमिका सबसे अहम है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा- नारी शक्ति के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। नारी शक्ति भी देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर अब आगे बढ़ रही है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि आज दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव का माहौल है, भारत शांति का संदेश फैला रहा है। हम पूरे ब्रह्मांड में शांति की कामना करते हैं। भारत की भूमिका शांति दूत की है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता की सार्वभौमिक सद्भाव की भावना को दर्शाती है। गरीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा देश में करोड़ों नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं...। *(दै.भा., 26.01.26)*

राजस्थान टीकाकरण में आगे निकला

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि 1992-93 में एनएफएचएस सर्वे के मुताबिक प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत मात्र 21.1 था, जो एनएफएचएस सर्वे 2020-21 में बढ़कर 80.4 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2024-25 में पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 91.8 प्रतिशत है। टीकाकरण के प्रभावी क्रियान्वयन से विगत वर्षों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तेजी से कम होकर राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। प्रदेश में बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को 10 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जिससे लगभग 11 गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। *(दै.भा., 17.03.20)*

कड़वा सचः नहीं सुधर रहे वाहन चालक

प्रदेश में वर्ष 2025 में 11,816 तो 2024 में 11,712 लोग सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही से कुचले गए। जबकि जयपुर कमिश्नरेट में वर्ष 2025 में 835 व 2024 में 850 लोगों के खून से सड़के लाल हुई। कड़वा सच यह है कि जयपुर की सड़कें चौड़ी हुई, फ्लाइओवर बने लेकिन चालकों की मानसिकता वहीं की वहीं है।

लोगों की सिर्फ रॉन्ग साइड ड्राइविंग और नशे में वाहन चलाना ही नहीं, बल्कि नियम तोड़ने की भी 'सनक' बन गई है। आलम यह है कि पिछले 7 सालों में लाइसेंस निलंबन की सिफारिशों में 14 गुना का भारी उछाल आया है। जहां वर्ष 2018 में मात्र 4,865 लोगों के लाइसेंस निलंबन की नौबत आई थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 56,122 पार कर गया। यह शहर के नागरिकों के ड्राइविंग सेंस के पतन और बेलगाम लापरवाही का आईना है। प्रशासन को सिर्फ चालान और जुर्माने से आगे बढ़कर अब 'जवाबदेही' भी तय करनी होगी। *(रा.प., 29.01.26, 14.02.26)*

वाहन चलाने में दक्ष तब मिलेगा लाइसेंस

प्रदेश के आरटीओ-डीटीओ ऑफिस से अब ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिल सकेगा, जो वाहन चलाने में दक्ष होंगे। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को आरटीओ इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर फेल-पास करेगा।

इसके लिए विभाग की ओर से जयपुर प्रथम सहित प्रदेश के 20 आरटीओ-डीटीओ आफिस में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लग चुके हैं। इसमें से 7 ऑफिसों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर ट्रायल शुरू हो चुके हैं। बाकी 13 ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर 31 मार्च से पहले ट्रायल लेना शुरू हो जाएगा। वहीं अगले एक साल में 19 ऑफिसों में भी ड्राइविंग ट्रैक लग जाएंगे। गौरतलब है, आरटीओ-डीटीओ आफिसों में दो साल बाद वापस से ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पटरी पर लौटे हैं। *(दै.भा., 16.03.26)*

नॉन-स्टॉप ड्राइव बन रही जानलेवा

हाल ही 14 फरवरी को जबलपुर से उज्जैन होते हुए खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए निकले 5 लोगों के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक की लगातार ड्राइव मौत का सफर बन गई। यह कोई अकेली घटना नहीं है, हाल ही के दिनों में लंबी दूरी की 'नॉन-स्टॉप ड्राइव' के कारण सड़क हादसे बढ़े हैं।

समय बचाने की जल्दबाजी में युवा एक ही दिन में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जिसका नतीजा नींद, थकान और एक पल की चूक, मंजिल से पहले ही यात्रा खत्म कर देती है। निजी ट्रेवल एजेंसियों के चालक आमतौर पर एक दिन में 250 से 300 किलोमीटर ही वाहन चलाते हैं, जबकि निजी गाड़ियों से लोग 800 से 1200 किलोमीटर तक ड्राइव का जोखिम उठा रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ गई है। *(रा.प., 23.02.26)*

थ्री डिजिट फर्जीवाड़े में की गई कार्रवाई

परिवहन विभाग में हुए थ्री डिजिट फर्जीवाड़े मामले में जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर में भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले 1100 से अधिक वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन) निलंबित कर दी है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन में 400 वाहनों का रिकॉर्ड फर्जी मिला।

ऐसे में इन वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। करीब 600 वाहनों को ही भौतिक सत्यापन में पास किया गया है। गौरतलब है कि फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद आरटीओ की ओर से जयपुर के सभी थ्री डिजिट वाहन स्वामियों को नोटिस देकर भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था। वाहनों के रजिस्ट्रेशन की पुराने रिकॉर्ड से जांच की गई थी। परिवहन विभाग की ओर से फर्जीवाड़े के मामले में गठित जांच कमेटी ने प्रदेश में 10 हजार वीआईपी नंबरों के हेरफेर की आशंका जताई है। *(रा.प., 18.01.26)*

पैदल यात्री सावधान : बाएं से नहीं, दाएं से चलो...

बचपन से हमें एक ही रट लगाई गई- 'सड़क पर हमेशा बाएं चलो।' यह लाइन हमारे दिमाग में इस कदर बस गई है कि सड़क पर आते ही बायां किनारा पकड़ लेते हैं। आम तौर पर लोग इससे अनजान है कि बाएं चलने का नियम सिर्फ गाड़ियों के लिए है, पैदल यात्रियों के लिए नहीं।

देश में सड़कों पर होने वाली कुल मौतों में 20% पैदल यात्रियों की होती है। वे पीछे से आती तेज गाड़ियों से बचने की कोशिश भी नहीं कर पाते। क्योंकि, जब आप बाएं चलते हैं तो खतरा आपकी पीठ पीछे होता है। इससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जब आप दाईं ओर पैदल चलते हैं, तो मौत की आंखों में आंखें डालकर समय रहते हटकर बच सकते हैं। बचपन की अधूरी सीख को पूरा करने का समय है 'गाड़ियों से चले बाएं, लेकिन पैदल चले दाएं'। निष्कर्षः दिशा कोई भी हो, नियम एक ही है- ट्रैफिक के विपरीत चलें। *(रा.प., 08.02.26)*

खौफ का पर्याय बनी प्रदेश की सड़कें

राज्य की सड़कें अब सफर का जरिया नहीं, बल्कि खौफ का पर्याय भी बन चुकी है। सरकारी फाइलों में भारी वाहनों के चालकों की ट्रेनिंग पूरी दिखाई जा रही है, लेकिन हकीकत में बिना किसी 'ट्रेनिंग टैकर' और कड़े इम्तिहान के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

इसका भयावह परिणाम यह है कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश की सड़कों पर 23,528 लोग कुचले गए। चालकों को लाइसेंस जारी करने वाले एक भी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना तो दूर, विभागीय कार्रवाई तक नहीं की गई। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राजस्थान में भारी वाहनों के चालकों का लाइसेंस बनाने के लिए एक भी ट्रेनिंग टैकर नहीं है। नियमानुसार ट्रेनिंग के बाद ही व्यावसायिक भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण किए जाने चाहिए। *(रा.प., 29.01.26)*

उपभोक्ता फैसले

चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर की लेटलतीफी...कंपनी भरेगी हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-तृतीय में राधेश्याम मीणा ने एविएशन ऑक्जीलरी सर्विस कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी 2019 के लोकसभा चुनाव में दौसा संसदीय क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के लिए उक्त कंपनी से 3 मई 2019 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बुक कराई और एनइएफटी के जरिए 7,83,520 रुपए जमा कराए। निर्धारित तिथि को हेलीकॉप्टर को सुबह 9 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन वह करीब 9.50 बजे रवाना हुआ और 12 बजे के बजाय सुबह 11.50 पर ही लौट आया। इससे परिवादी को चुनाव प्रसार के लिए कम समय मिला, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने एविएशन ऑक्जीलरी सर्विस कंपनी की सेवा में कमी माना और सेवा प्रदाता कंपनी व उसके प्रबंध निदेशक को सेवा में 45 मिनट का कम समय देने के बदले 1,95,880 रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस लौटाने और साथ ही 21 हजार रुपए हर्जाने स्वरूप देने के निर्देश दिए हैं। *(रा.प. एवं दै.भा., 08.03.26)*

पैसेंजर पायलट का बैग गुम, एयरलाइंस को देना होगा हर्जाना

विद्याधर निवासी अमन अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-तृतीय में अमेरिकन एयरलाइंस व एतिहाद एयरवेज कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी अमन अग्रवाल अमेरिका से प्रशिक्षित कामर्शियल पायलट का प्रशिक्षण लेकर भारत लौट रहे थे। 19 जुलाई 2023 को यात्रा करने के लिए टिकट बुक किया। जिसकी उड़ान ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयार्क व आबूधाबी होते हुए नई दिल्ली तक थी, लेकिन पहली फ्लाइट में देरी होने से उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई और उन्हें दूसरी फ्लाइट से भेजा। इस प्रक्रिया में उनका चेक-इन सामान सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ। नई दिल्ली पहुंचने के बाद उनके दोनों बैग नहीं मिले। बाद में एक बैग मिल गया, लेकिन दूसरा बैग जिसमें पायलट लाइसेंस, लॉगबुक, मेडिकल रिकॉर्ड व वीजा सहित कई महत्वपूर्ण कागज थे नहीं मिला।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने पायलट का बैग गुम होने को अमेरिकन एयरलाइंस व एतिहाद एयरवेज कंपनी की गंभीर लापरवाही और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना। आयोग ने विपक्षी कंपनियों पर 11 हजार रुपए हर्जाना लगाया और साथ ही निर्देश दिया कि परिवादी अमन अग्रवाल के खोए सामान की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 1,30,572 रुपए ब्याज सहित दें।

(दै.भा., 21.03.26)

उपभोक्ता अदालतों को प्रभावी बनाने पर जोर

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जयपुर स्थित कांस्टीट्यूशनल क्लब में 'सुरक्षित उत्पाद-आश्वस्त उपभोक्ता' थीम पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही, अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि आयोगों के लिए उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि अब जिला उपभोक्ता आयोग 50 लाख रुपए तक के मामलों का निस्तारण करने में सक्षम है, जिससें न्याय प्रक्रिया त्वरित होगी। इससे उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि नकली ब्रांडों की बढ़ती बिक्री आज बाजार में एक बड़ी चुनौती है, जिसका मुकाबला केवल जन-जागरूकता से ही संभव है। उन्होंने विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जैसे नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोगों में आने वाले आमजन के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उपभोक्ता हेल्पलाइन 14435 को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को त्वरित समाधान मिल सके। *(रा.प., 16.03.26)*

ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी का खेल

ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ता चलन अब उपभोक्ताओं के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। ऑनलाइन वेबसाइट आकर्षक तस्वीरों और भारी छूट का लालच देकर ग्राहकों को सामान बेच रही है। लेकिन खराब वस्तु लौटाने के बाद भी धन वापसी नहीं कर रही।

कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि रिटर्न लेने के बावजूद उनके पैसे अटका दिए गए और ग्राहक सेवा केवल आश्वासन दे रही है। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे पीड़ितों में आक्रोश और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को सबसे पहले कंपनी को लिखित नोटिस भेजना चाहिए और सभी प्रमाण सुरक्षित रखने चाहिए। यदि तय समय में राशि वापस नहीं आती है तो जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। *(रा.प., 15.02.26)*

स्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)